नईदुनिया

संपादकीय

पहलगाम में चूक की जवाबदेही

इसमें दो राय नहीं कि पहलगाम के भीषण आतंकी हमले ने देश के अंतर्मन पर गहरे जख्म छोड़े हैं। नि:संदेह, निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कई सवाल हमारे सामने छोड़ गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कश्मीर का दौरा किया। उस आतंकी हमले के बाद जिसमें छब्बीस लोग मारे गए थे। नि:संदेह, उनका यह दौरा हमारे इस सैन्य संकल्प की अभिव्यक्ति है कि हमारी सेना आम जन की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां लोगों ने दशकों आतंक की त्रासदी झेली है, वहां प्रतीकात्मक जवाबदेही से आगे ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से आतंकवादियों ने उस क्षेत्र को अपने आतंक का निशान बनाया, जो जम्मू-कश्मीर के अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में शामिल था। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस हमले को लेकर कोई खुफिया अलर्ट क्यों नहीं मिल पाया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त हुआ है। दरअसल, सुरक्षा चूक की ऐसी घटनाएं सिस्टम की तैयारियों के प्रति जनता के भरोसे को प्रभावित करती हैं। इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप किया। इस संकटपूर्ण स्थिति में उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही रोकना प्राथमिकता समझा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तुरंत जम्मू-कश्मीर पहुंचे। वहीं शाह का तुरंत घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण घटना की गंभीरता को ही रेखांकित करता है। अब चाहे ये प्रयास कितने भी तात्कालिक व ईमानदार क्यों न हों, वे प्रणालीगत सुधार के विकल्प नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि हर अपराधी को पकड़ने के लिये सरकार कृतसंकल्प है। लेकिन इस तरह के आश्वासन केवल अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। बेहतर होता कि हम पहले ही ऐसी चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करते कि परिंदा भी पर न मार सकता। निश्चित रूप से इस तरह के आतंकी हमले का व्यापक परिदृश्य हमें आत्ममंथन को विवश करता है।

बहरहाल, पहलगाम आतंकी हमले से हुई जनहानि तमाम सवालों को जन्म देती है। हर किसी संवेदनशील मन में घटनाक्रम को लेकर अनेक प्रश्न उभरते हैं। आम विमर्श में यह मुद्दा उठता रहा है कि जम्मू-कश्मीर के इस संवेदनशील क्षेत्र में सेना की उपस्थिति क्यों नहीं थी। आखिर इस हमले की भनक हमारे खुफिया तंत्र को क्यों नहीं लगी। जम्मू-कश्मीर देश का सीमावर्ती व संवेदनशील क्षेत्र है। दशकों की आतंकी घटनाओं के चलते इस क्षेत्र में सेना, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा स्थानीय पुलिस की उपस्थिति देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है। सवाल यह भी है कि आखिर खुफिया एजेंसियों से किस स्तर पर और क्यों चूक हुई। आखिर स्थानीय व विदेशी आतंकवादी इतनी आसानी से हमारे सुरक्षा चक्र को भेदने में कैसे सफल रहे? ऐसे तमाम सवाल हमारे नीति-नियंताओं से पारदर्शी जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सार्वजनिक रूप से बयान देने से काम चलने वाला नहीं है। हमें सुरक्षा व्यवस्था व खुफिया तंत्र की उन तमाम खामियों को दूर करना होगा, जिनके अभाव में आतंकवादी अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में सफल हो सके। निस्संदेह, कश्मीर यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने सुरक्षा बलों के बीच ऑपरेशनल समन्वय की समीक्षा की। लेकिन राष्ट्र और कश्मीरी सिर्फ प्रोटोकॉल को सख्त करने से कहीं अधिक चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के आलोक में खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को सक्षम बनाने, तेज प्रतिक्रिया ढांचे के निर्माण और सुरक्षा तंत्र की मजबूती को मूर्त रूप देने की जरूरत है। कश्मीर को लेकर हमारे दांव हमेशा ऊंचे होते हैं, अब चाहे वे सैन्य, भावनात्मक और राजनीतिक रूप से हों। हमें पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोने वाले लोगों के दर्द को संवेदनशील ढंग से महसूस करना चाहिए। आज वास्तविक स्थिति में बदलाव की जरूरत है ताकि हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को संबल मिल सके।

सामुदायिक हिंसा का बढ़ता खतरा

-प्रभुनाथ शुक्ल

जम्मू -कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह निर्दोष पर्यटकों का नरसंहार किया, वह मानवता के खिलाफ है। इस हिंसा में 26 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। आतंकवादियों ने सिर्फ हिन्दुओं को निशाना बनाया और उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारीं । हालांकि की कश्मीर में इस नरसंहार को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस बात पर भी गुस्सा है कि हमले में सिर्फ हिन्दू मारे गए। लोगों का कहना है कि पर्यटकों की जान बचाने के लिए एक मुस्लिम भी मारा गया। अब पूरा कश्मीर पीड़ित परिवारों के साथ है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संस्थाओं ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है।

भारत में हिन्दुओं पर सामुदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अपने ही देश में बहुसंख्य हिन्दू हिंसक घटनाओं का शिकार हो रहा है। वैसे सामुदायिक और नस्लीय हिंसा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारत के आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हमले और हिंसा बढ़ गई हैं। नेपाल जैसे देश में भी रामनवमी जुलूस पर हिंसा को अंजाम दिया गया। भारत के पड़ोसी इस्लामिक देश में हिन्दुओं की स्थिति बद से बदतर है, जबकि ये कभी भारत के हिस्सा थे। यहाँ हिन्दुओं पर लगातार धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। आतंकवाद से लड़ रहे भारत के सामने सामुदायिक हिंसा की घटनाएं बड़ी चुनौती बन रहीं हैं। सबसे अहम मुद्दा यह है कि अपने देश में ही हिन्दू बाहुल्य होने के बाद भी वह सामुदायिक हिंसा का शिकार बन रहा है। जबकि चीन में उइगर मुसमानों का दमन किसी से छुपा नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश खामोश हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुआ नरसंहार इसका ताज़ा उदाहरण है। भारत में इस तरह की हिंसा के पीछे वोट बैंक के लिए राजनीतिक तुष्टिकरण सबसे बड़ी समस्या है।

भारत में हिन्दुओं पर हिंसक हमले इस्लामिक आतंकवाद की एक सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान में हिन्दुओं की आबादी गिनती पर आ गई है। भारत में इस तरह के सामुदायिक और धार्मिक दंगे भड़काने के लिए पाकिस्तान मूल रूप से जिम्मेदार है। लेकिन हम इस तरह की बात कर अपनी जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकते हैं। भारत इस्लामिक आतंकवाद से तो हमेशा से पीड़ित रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में राजनैतिक कारणों और उसके फैसलों से देश में सामुदायिक हिंसा, प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गईं हैं। दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति नफरत और डर का माहौल पैदा हुआ है। इस तरह की सामुदायिक हिंसा के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, सोशलमीडिया और धार्मिक कारण मुख्य हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं देश के धार्मिक और सांप्रदायिक तानेबाने को विभाजित करती दिखती हैं।

जम्मू -कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह निर्दोष पर्यटकों का नरसंहार किया, वह मानवता के खिलाफ है। इस हिंसा में 26 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। आतंकवादियों ने सिर्फ हिन्दुओं को निशाना बनाया और उनका धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारीं । हालांकि की कश्मीर में इस नरसंहार को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस बात पर भी गुस्सा है कि हमले में सिर्फ हिन्दू मारे गए। लोगों का कहना है कि पर्यटकों की जान बचाने के लिए एक मुस्लिम भी मारा गया। अब पूरा कश्मीर पीड़ित परिवारों के साथ है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संस्थाओं ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है।

इस साजिश के पीछे हाल में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कियानी की तरफ दिया गया वह उकसाऊ बयान भी अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने भारत व हिन्दुओं के खिलाफ भड़काने वाला बयान दिया था। कियानी के बयान के ठीक कुछ दिन बात पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें पर्यटकों का धर्म पूँछ कर नरसंहार किया गया। यह पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वह भारत से सीधी जंग में कभी नहीं जीत सकता है। ऐसी स्थिति में वह हिन्दुओं को निशाना बनाकर भारतीय मुसलमानों का मसीहा बनना चाहता है। खैबर पख्तून में बलोच आर्मी की तरफ से किए ट्रेन हाईजैक के पीछे वह भारत का हाथ मानता है। जिसकी वजह से वह बौखलाया था और बदले के लिए बेताब था।

उधर कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर आहिस्ता-आहिस्ता विकास की मुख्यधारा में लौट रहा है। आतंकी घटनाएं कम हुईं हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। सेबों की खेती लहलाहने लगी है। यह सब देख पाकिस्तानी फ़ौज में बौखलाहट है जिसकी वजह से वह इस तरह की सामुदायिक हिंसा की साजिश रच रहा है। कश्मीर में सामुदायिक हिंसा की यह पहली घटना नहीं है। आतंकवादियों ने पुलवामा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। कश्मीर में साल 2019 के बाद धारा 370 लागू होने के बाद यह पहली सबसे बड़ी आतंकी नरसंहार की घटना है। दूसरा अहम कारण ये कि कश्मीर के राजनैतिक और अलगाववादी कभी शान्ति और विकास नहीं चाहते हैं। क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद उनकी तमाम स्वतंत्रता जहाँ बाधित हुईं, वहीं आर्थिक नुकसान हुआ है। वहां के राजनेताओं और अलगाववादियों का पाकिस्तान प्रेम दुनिया में जगजाहिर है। इसके बावजूद धारा 370 का खात्मा, तीन तलाक कानून और वक्फ संशोधन जैसे राजनैतिक फैसले इस आग में घी का काम किया है। हालांकि यह आम मुसलमानों और कश्मीरियों की सोच नहीं है। यह सिर्फ अलगाववादियों की सोच है।

इस घटना में केंद्र और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। जब वहां काफी तादात में पर्यटकों की आमद हो रहीं थी तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सेना और राज्य पुलिस के जवानों की तैनाती क्यों नहीं की गईं। कियानी के विभाजनकारी संदेश को हमारी सरकार, खुफ़िया एजेंसिया और सुरक्षा एजेंसिया नहीं समझ पाईं। ऐसे संवेदनशील पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम होने चाहिए थे। राज्य में इस तरह की घटनाएं पर्यटन उद्योग और उसकी संभावनाओं पर पानी फेरती हैं। हम अपनी चूक और नाकामियों से नहीं बच सकते। यह गंभीर मंथन का विषय है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हमें सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखना होगा। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। यह हमला भारत की आत्मा पर है यह राजनीति का वक्त नहीं है। सारा देश गुस्से में है। रणनीति बनाकर पाकिस्तान और आतंकवाद को सबक सिखाने की जरूरत है। कश्मीर के पूर्व बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिन्दुओं को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा रामनवमी जुलूस पर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश भी सुनियोजित तरीके से हिन्दुओं पर हमले हुए। उत्तर प्रदेश में संभल किसी से छुपा नहीं है। वहां किस तरह हिन्दुओं का उत्पीड़न हुआ, उसे कौन नहीं जानता।

पहलगाम की घाटी में इंसानियत की हत्या

- डॉ. सत्यवान सौरभ

जम्मू-कश्मीर के पहलगाँव में हुए आतंकी हमले में जहाँ हिन्दू पर्यटकों को उनका नाम गोली मार दी गई। ये हमला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान के आधार पर की गई घृणा और आतंक का प्रतीक है तो है ही, वहीं इंसानियत की भी हत्या है। यह घटना भारत की एकता, नागरिक सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता पर चोट बताकर चेतावनी देती है कि यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगला शिकार कोई और होगा। यह घटना शोक प्रकट करने की बजाय जवाबदेही, निर्णायक कार्रवाई और सामाजिक चेतना की मांग करती है, ताकि आतंक के आगे इंसानियत बार-बार न मरे।

22 अप्रैल की सुबह के कुछ शांत लम्हे। जम्मू-कश्मीर के पहलगाँव में बर्फीली वादियाँ पर्यटकों का स्वागत कर रही थीं। नवविवाहित जोड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग ङ्क सबको उम्मीद थी कि कश्मीर की हवा में सुकून मिलेगा, तनाव से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन तभी आतंक की आहट हुई। बंदूकें गरजीं। और उस वादी में जहाँ बर्फ गिरती है, अब खून बहा। राजस्थान से आया एक नवविवाहित दंपत्ति भी उन्हीं पर्यटकों में था। दोनों ने अभी पांच दिन पहले ही शादी की थी। वो अपने हनीमून के लिए कश्मीर आए थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। आतंकियों ने गाड़ी रोकी, नाम पूछा, पहचान की और फिर गोली मार दी। युवक हिन्दू था। बस यही उसके मरने की वजह बन गई। सिर में गोली लगी। मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी, जिसके हाथों की मेंहदी अभी भी गीली थी, स्तब्ध खड़ी थी। शोक से ज़्यादा वो एक अनकहे डर में जमी हुई थी-जैसे समय वहीं थम गया हो। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। यह योजनाबद्ध नरसंहार था। एक सोच के तहत, एक धर्म के आधार पर। आज आतंकवाद महज़ क्षेत्रीय या वैचारिक लड़ाई नहीं रह गया है। यह अब धार्मिक पहचान को मिटाने का एक उपकरण बन चुका है। यह हत्या बताती हैं कि कुछ तत्व अब यह तय कर चुके हैं कि कौन जिएगा, कौन मरेगा और यह फ़ैसला नाम पूछकर किया जाएगा। क्या यही इंसानियत है, क्या यही 'कश्मीरियत' है, जिसके नाम पर हम वर्षों से शांति की दुहाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उस पत्नी की तस्वीर वायरल हुई, जो अपने पति के शव को निहार रही थी। न चीख, न रोना, न प्रतिरोध। बस एक स्थिर मौन- जो पूरी व्यवस्था पर सबसे कठोर आरोप बन गया। उस मौन में एक सवाल छुपा है हमने क्या ग़लत किया क्या एक जोड़े का कश्मीर आना, उसकी सुंदरता देखना, उसकी वादियों से प्यार करना अब गुनाह बन चुका है। हमें समझना होगा कि इस तस्वीर में केवल एक महिला नहीं थी, बल्कि उस पूरे राष्ट्र की आत्मा थी, जख़्मी, असहाय और शर्मसार।

हर हमले के बाद सरकार की ओर से एक तैयार स्क्रिप्ट आती है- निंदा, मुआवज़ा, जाँच। लेकिन जवाबदेही कहीं नहीं होती। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि घाटी में आतंकियों को खुलेआम चलने-फिरने की छूट कैसे मिलती है। वे नाम पूछकर कैसे किसी को गोली मार सकते हैं और फिर बच निकलते हैं। क्या पर्यटन सीजन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। क्या जम्मू-कश्मीर प्रशासन को यह नहीं पता कि ऐसे हमले पर्यटन, अर्थव्यवस्था और भारत की एकता ङ्क तीनों पर हमला करते हैं। जब भी भारत आतंक के ख़िलाफ़ सख़्ती दिखाता है तो मानवाधिकार की दुकानें खुल जाती हैं। दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क ङ्क हर जगह के तथाकथित बुद्धिजीवी अचानक 'संवेदना' से भर जाते हैं। लेकिन जब किसी हिंदू नागरिक को सिर्फ उसके नाम के कारण सिर में गोली मारी जाती है, तब यही आवाज़ें खामोश हो जाती हैं। क्यों? क्या एक विशेष समुदाय के पीड़ितों के लिए ही संवेदना है। क्या हिन्दू होना अब मानवाधिकार के चश्मे से अदृश्य हो जाना है। पहलगाँव हमला केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह भारत की आत्मा पर हमला है। यह संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। यह भारत की एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती है। यदि हमने इस चुनौती को केवल ट्वीट और मोमबत्तियों से उत्तर दिया, तो अगला निशाना कोई और शहर, कोई और नाम, कोई और नवविवाहित होगा।

हमेशा की तरह, इस हमले के पीछे जिस आतंकी संगठन का नाम आया - 'द रेजिस्टेंस फ्रंट'- वह लश्कर-ए-तैयबा का ही नया अवतार है। इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अभी भी 'आतंकवाद का शिकार देश' बना बैठा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप- सभी को यह साफ-साफ कहना चाहिए कि धार्मिक आधार पर नागरिकों की हत्या केवल एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक मानवता का संकट है।

भारत को अब दो टूक निर्णय लेने की ज़रूरत है। कश्मीर में आतंक का सामना केवल पुलिस नहीं कर सकती, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। अलगाववाद की नर्म परतों को उखाड़ फेंकना होगा। धार्मिक पहचान के नाम पर फैलाई जा रही नफ़रत को सामाजिक स्तर पर भी चुनौती देनी होगी। इसके साथ-साथ, हमें यह तय करना होगा कि कश्मीर में पर्यटन केवल स्वर्ग दिखाने का सौदा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का सेतु है और इस सेतु की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है।

हर आतंकी हमले के बाद हम कुछ दिन दुखी होते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन उस स्त्री के लिए, जिसने अपने पति को खोया, वह महिलाएं जिन्होंने अपने सुहाग, वह बच्चे जिन्होंने अपने पिता और वह बहनें जिन्होंने अपने भाई खोए हैं। जो लहूलुहान सपनों के साथ अकेले रह गए हैं, उन सभी के लिय यह घटना एक जीवन भर का घाव है। हमारी संवेदना केवल सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि कब तक हम अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाएँगे। कब तक हम आतंकी हमलों पर केवल मोमबत्तियाँ जलाते रहेंगे?

आजकल

रिश्वतखोरों पर कंसे शिकंजा

और राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद देश में भ्रष्टाचार रूपी विषबेल फैलती ही जा रही है जिसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक शामिल पाए जा रहे हैं। मात्र एक सप्ताह के ही उदाहरण निम्न में दर्ज हैं । 18 अप्रैल को 'फतेहाबाद' (हरियाणा) में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने 'एक्साइज डिपार्टमैंट' के असिस्टैंट एक्साइज एंड टैक्सेशन मैनेजर 'कृष्ण लाल वर्मा' को 15,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

19 अप्रैल को 'कैथल' (हरियाणा) में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पूर्व पार्षद 'कमल मित्तल' को शिकायतकर्त्ता से 4 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 21 अप्रैल को सतर्कता विभाग ने 'फगवाड़ा' (पंजाब) के सहायक टाऊन प्लानर 'राजकुमार' व एक निजी आर्कीटैक्ट 'राजेश कुमार' को शिकायतकर्त्ता से 50,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा।

21 अप्रैल को ही सतर्कता विभाग ने ब्लाक विकास एवं पंचायत कार्यालय 'बरनाला' में तैनात पंचायत सचिव 'गुरमेल सिंह' को एक ठेकेदार की शिकायत पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। 21 अप्रैल को ही अधिकारियों ने 'सवाई माधोपुर' (राजस्थान) में 'रवांजना डूंगर' थाने में तैनात हैड कांस्टेबल 'रणजीत सिंह' को शिकायतकर्त्ता के विरुद्ध दर्ज एक मामला रफा-दफा करने के आरोप में उससे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 22 अप्रैल को 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' ने 'मडगांव' में 'कोंकण रेलवे पुलिस थाने' में 25000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में एक इंस्पैक्टर 'सुनील गुडलर' तथा कांस्टेबल 'हुसैन शेख' को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व 2011 में भी 'गुडलर' को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करके निलंबित किया गया था परंतु बाद में वह बहाल हो गया था। 22 अप्रैल को ही 'झज्जर' (हरियाणा) में विजीलैंस विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के जे.ई. 'अंकित' को एक ठेकेदार के 15 लाख रुपए के बिल पास करवाने के नाम पर 48,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 23 अप्रैल को 'फरीदाबाद' (हरियाणा) के जिला राजस्व कार्यालय में तैनात क्लर्क 'राजेश' को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने शिकायतकर्त्ता से 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 23 अप्रैल को ही सतर्कता विभाग की टीम ने 'पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड' में तैनात जूनियर इंजीनियर 'जसमेल सिंह' को 30,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

बढ़ता तापमान इंसानों के लिए खतरे की घंटी

मुकेश तिवारी

पूरी दुनिया के वैश्विक तापमान में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है। यहां तक कि ऋतु चक्र में भी बदलाव रहा है। पृथ्वी के औसत तापमान में भी वृद्धि हो रही है, यह सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि गंभीर पर्यावरणीय संकट के लक्षण है।

गौरतलब है कि पहले जहां गरमी का प्रकोप सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित रहता था। लेकिन अब यह शनै -शनै पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने लगा है लेकिन हम कथित विकास की मदहोशी से जाग नहीं पा रहे जबकि तल्ख सच्चाई यह है। कि पर्यावरण या जैव विविधता संरक्षण सीधे-सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा मसला है। समूचे विश्व में 2 लाख किस्म के पौधे और 10 लाख 50 हजार प्रजातियों के प्राणी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ़ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में जीव जंतुओं की 47677 विशेष प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक यानी की 15890 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।

साल दर साल गर्मी कहर बरपाती जा रही है। इस साल भी अप्रैल के महीने में तापमान 44 डिग्री पर पहुंच चुका है। पृथ्वी का तेजी से बढ़ता तापमान सिर्फ मानव जाति के लिए ही खतरे की घंटी नहीं है बल्कि वन्य जीवों, पक्षियों और समूचे इकोसिस्टम पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। अमेरिका के कोलारेडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ़ साइंस में प्रकाशित शोध से सचेत किया है कि जलवायु संकट की वजह से पिघलती बर्फ के कारण समुद्र का जलस्तर इस सदी के अंत तक

दुगने से भी ऊपर निकल जाएगा। शोधकर्ताओं ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर के लिए दो महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। पहला ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी पर हवा और पानी का तापमान बढ़ना , और दूसरा जमीनी बर्फ के तेजी से पिघलने से समुद्री जल स्तर में लगातार इजाफा होना।

वर्ल्ड वेदर एटिब्यूशन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से ही तापमान में वृद्धि,भारी बारिश और तेज तूफान जैसे ज्यादा और गंभीर मौसम का सामना करना पड़ा रहा है। मैक्सिको की खाडी स्थित लुइसियाना का डेलाक्रोइस शहर देश दुनिया में चर्चा का विषय बना चुका है उक्त शहर शने -शने समुद्र में समा रहा है।

पिछले 100 साल में लुइसियाना की 1880 वर्ग मीटर भूमि समुद्र में डूब चुकी है। स्थिति कुछ ऐसी है कि 17 वर्ग मील भूमि हर साल डूब रही है। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 100 साल में समुद्र का पानी भरने की रफ्तार पिछली 27 सदियों से अधिक है।

वैज्ञानिकों की माने तो यदि समय रहते धरती का तापमान रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर 50 से 130 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। कुछ समय पहले कैंब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि आने वाले एक दो वर्ष में अटलांटिक समुद्र की बर्फ पूरी तरह से पिघलाकर समाप्त हो जाएगी। विकास के नाम पर प्रकृति से बढ़ती छेड़छाड़ का खमियाजा मानव जाति से लेकर वन्यजीव, पक्षियों को अपने विनाश से चुकाना पड़ सकता है। खासकर घरों,फैकिटयों और गाड़ियों में तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से निकली कार्बन डाइऑक्साइड व पराबैंगनी विकिरण से हवा, पृथ्वी, पानी गर्म हो रहे है।

बीती आधी सदी में कोयला - पेट्रोलियम के धुंए ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को खतरनाक हद तक पहुंचा दिया है। वैज्ञानिकों का दो-टूक शब्दों में कहना है कि सामान्य तौर पर सूर्य की किरणों से आने वाली ऊष्मा का एक हिस्सा वायुमंडल में जरूरी ऊर्जा देकर अतिरिक्त विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह से टकराकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। लेकिन वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस लौटने वाली अतिरिक्त उष्मा को भी सोख ले रही है। जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है।

वर्षा जल की अधिकता वाले जंगलों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पराबैंगनी विकिरण को सोखने और छोड़ने का संतुलन बिगबता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति वर्ष तकरीबन 73 लाख हेक्टर जंगल नष्ट हो रहे हैं। ज्यादातार रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग, वृक्षों के काटने से मिट्टी की दशा भी बिगड़ रही है। वहीं जंगली और समुद्री जीव का अंधाधुंध शिकार भी संतुलन को खराब करता है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या भी इसमें इजाफा कर रही है। 20वीं सदी में में दुनिया की जनसंख्या लगभग 1.7 अरब थी, लेकिन अब 6 गुना ज्यादा 7.5 अरब से ज्यादा है।